

ग्रताधारण

EXTRAORDINARY

भाग I--खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित



PUBLISHED BY AUTHORITY

'40 [53] 'Ne. ≠31 नेई दिल्ली. इतिवार, जुलाई 1, 1972/म्राषाइ 10, 1894 NEW DELHL SATURDAY, JULY 1, 1972'ASADHA 10, 1894

इस जाब में भिन्न प्रष्ठ सख्या दो जार्ता है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

16.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July 1972

No. RS. 7/1/70-L(1).—The following amendments to the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha) as adopted by the Kajya Sabha at its sitting held on the 1st June, 1972, are hereby published for general information:—

Rule 180

- 1. For sub-rule (5), the following sub-rule be substituted, namely:-
 - The proposed matter shall be raised after the questions and the laying of papers, if any, on the Table and before any other item in the list of business is taken up and at no other time during the sitting of the Council.

Rule 204

- 2. For rule 204, the following rule be substituted, namely:-
 - 204. Committee on Subordinate Legislation.—There shall be a Committee on Subordinate Legislation to scrutinize and report to the Council whether the powers to make rules, regulations, bye-laws, schemes or other statutory instruments conferred by the Constitution or delegated by Parliament have been properly exercised within such conferment or delegation, as the case may be.

Rule 209

- 3. For rule 209, the following rule be substituted, namely:-
 - 209. Duties of Committee.—After each rule, regulation, bye-law, scheme or other statutory instrument (hereinafter referred to as the 'order')-framed in pursuance of the Constitution or the legislative functions: delegated by Parliament to a subordinate authority and which is required to be laid before Parliament, is so laid before the Council, the Committee shall, in particular consider—
 - (i) whether the order is in accord with the provisions of the Constitution or the Act pursuant to which it is made;
 - (ii) whether the order contains matter which in the opinion of the Committee should more properly be dealt with in an Act of Parlianums;
 - (iii) whether the order contains imposition of taxation;
 - (iv) whether the order directly or indirectly bars the jurisdiction of the court;
 - (v) whether the order gives retrospective effect to any of the provisions in respect of which the Constitution or the Act does not expressly give any such power;
 - (vi) whether the order involves expenditure from the Consolidated Fund of India or the public revenues;
 - (vii) whether the order appears to make some unusual or unexpected use of the power conferred by the Constitution or the Act pursual; which it is made;
 - (viii) whether there appears to have been unjustifiable delay in its publication or laying the order before Parliament;
 - (ix) whether for any reason the form or purport of the order calls for any elucidation.
- 4. After rule 212, the following new rules be inserted, namely:-

CHAPTER XVII-A

Committee on Government Assurances

- 212(A). Committee on Government Assurances.—There shall be a Committee on Government Assurances to scrutinize the assurances, promises, undertakings etc., given by Ministers, from time to time, are the floor of the Council and to report on—
 - (a) the extent to which such assurances, promises, undertakings have been implemented; and
 - (b) when implemented whether such implementation has taken places within the minimum time necessary for the purpose.
- 212(B). Constitution of the Committee.—(1) The Committee shall consist of ten members who shall be nominated by the Chairman.
- (2) The Committee nominated under sub-rule (1) shall hold office until a new Committee is nominated.

- (3) Casual vacancies in the Committee shall be filled by the Chairman.
- 212(C). Chairman of the Committee.—(1) The Chairman of the Committee shall be appointed by the Chairman from amongst the Members of the Committee;
- Provided that if the Deputy Chairman is a member of the Committee he shall be appointed Chairman of the Committee.
- (2) If the Chairman of the Committee is for any reason unable to act, the Chairman may similarly appoint another Chairman of the Committee in his place.
- (3) If the Chairman of the Committee is absent from any meeting, the Committee shall choose another member to act as Chairman of the Committee for that meeting.
- 212(D). Quorum.—(1) In order to constitute a meeting of the Committee, the quorum shall be five.
- (2) The Chairman of the Committee shall not vote in the first instance but in the case of an equality of votes on any matter, he shall have, and exercise, a casting vote,
- 212(E). Power to take evidence or call for papers, records or documents.—
 (1) The Committee shall have power to require the attendance of persons or the production of papers or records, if such a course is considered necessary for the discharge of its duties:
- Provided that Government may decline to produce a document on the ground that its disclosure would be prejudicial to the safety or interest of the State.
- (2) Subject to the provision of this rule, a witness may be summoned by an order signed by the Secretary and shall produce such documents as are required for the use of the Committee,
- (3) It shall be in the discretion of the Committee to treat any evidence tendered before it as secret or confidential.
- 212(F). Presentation of the Report.—The Report of the Committee shall be presented to the Council by the Chairman of the Committee or, in his absence, by any member of the Committee.
- 212(G). Regulation of Procedure.—The Committee shall determine its own procedure in connection with all matters connected with the consideration of any question of assurances, promises, undertakings, etc. in the Committee.

B. N. BANERJEE, Secy.

राज्य सभा सचिवालय

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1972

संस्था द्वार एस 7/1/7 -एल (1).-राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के निम्नलिखित संशोधन, जिस रूप में वे राज्य सभा द्वारा 1 जून, 1972 को प्रपनी वैठक में स्वीकृत किये गये, एतदहारा सामान्य सूचनार्थ प्रकाणित किये जाते हैं।-

नियम 180

- 1. उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाय, प्रर्थात्:--
 - (5) प्रस्थापित विषय प्रश्नों श्रौर यदि सभा पटल पर रखे जाने के लिये कोई पत्र हों तो उनके सभा पटल पर रखे जाने के बाद तथा कार्यविल में दर्ज किसी

किसी भ्रन्य मद के लिये जाने से पहले उठाया जायेगा और राज्य सभा की चैठक के दौरान भ्रन्य किसी समय नहीं उठाया जायेगा।

नियम 204

2. नियम 204 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, ग्रर्थात्:-

204. स्रशीतस्य विशान संबंधी सिमिति.— स्रधीनस्थ विधान संबंधी एक सिमिति इस बात की परिनिरीक्षा करने स्रौर राज्य सभा को यह प्रतिवेदन करने के लिये होगी कि क्या इत नियमों, विनियमों, उपविधियों, योजनास्रों स्रथवा स्रन्य परिनियत सनेखों को बताने की संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग, यथास्थिति उस परिदान या प्रत्यायोजन के स्रन्तर्गत उचित रूप से किया गया है।

नियम 209

- 3. नियम 209 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, ग्रयीन:-
- 209. सिमिति के कर्त य.—संविधान के स्रथवा संसद द्वारा किसी स्रधीनस्थ प्राधिकारी को अत्यायोजित वैधानिक कृत्यों के अनुसरण के बनाये गये प्रत्येक नियम, विनियम, उपविधि, योजना स्रयवा ग्रन्य परिनियत संलेख के (जिसे इसके पश्चात् 'स्रादेश' कहा गया है) जिसको संसद के समक्ष रखा जाना स्रपेक्षित हो, राज्य सभा के समक्ष इस प्रकार रखे जाने के बाद, सिमिति विगेष क्ष्य से इस बात पर विचार करेगी कि :—
 - (1) क्या वह ग्रादेश संविधान के उपबंधों ग्रयवा उस ग्रिधितियम के ग्रनुकूत है जिसके ग्रनुसरण में वह बनाया गया है ;
 - (2) क्या उस ग्रादेश में ऐसा विषय ग्रन्तिविष्ट है जिसे समिति की राय में ग्रधिक समुचित ठंग से संसद के ग्रिधिनियम के द्वारा निपटाया जाये;
 - (3) क्या उस म्रादेश में कोई करारोपण म्रन्तर्विष्ट है ;
 - (4) क्या उस म्रादेश से न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रुकावट होती है;
 - (5) क्या वह म्रादेश उन उपवंधों में से किसी को भूतलक्षी प्रभाव देता है जिसके संबंध में संविधान म्रथवा म्रधिनियम स्पष्ट रूप से ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता ;
 - (6) क्या उस म्रादेश में भारत की संचित निधि या लोक राजस्व में से व्यय ग्रन्तर्गस्त है;
 - (7) क्या उस आदेश में संविधान अथवा उस प्रिधितियम हारा प्रदत्त शक्तियों का, जिसके अनुसरण में वह बनावा गया है, प्रशतास्य प्रवण अप्रयाणित उपयोग निव्धा गया प्रशति होता है;

- (8) क्या उस प्रादेश के प्रकाशन में या उसके संसद् के समक्ष रखे जाने में प्रनुवित विलम्ब हम्मा प्रतीत होता है;
- (9) क्या किसी कारण से श्रादेश के रूप या श्रभिप्राय के किसी विशुद्धिकरण की श्रावश्यकता है।"
- 4. नियम 212 के पश्चात् निम्नलिखित नये नियम भ्रन्तःस्थागित किये जायें, श्रर्थात्:--

ग्रध्याय 17-क

सरकारी ब्राइबासनों संबंधी समिति

- 212(क) **सरकारी श्राहवासनों सबक्षी समिति.**—-राज्य सभा में मंत्रियों द्वारा समय—-समय पर दिये गये श्राहवासनों, बचनों, प्रतिजाशों श्रादि की परिनिरीक्षा कर ने श्रीर निःनलिखित. **बा**लों के बारे में प्रतिवेदन करने के लिये एक समिति होगी कि:—-
 - (क) ऐसे श्राक्ष्यासन, वचन, प्रतिज्ञाएं श्रादि कहां तक कार्यान्वित कर दिये गये हैं ; ग्रीर
 - (ख) यदि वे कार्यान्वित कर दिये गये हैं तो क्या यह कार्यान्वित इस काम के लिये श्रावण्यक न्युनतम समय में हुआ है।
- 212 (ख) सिमिति का गठन-.-(1) सिमिति में 10 सदस्य होंगें जो सभाषित द्वारा नाम -निर्देशित किये जायेगे।
- (2) उपनियम (1) के श्रधीन नाम-निर्देशित समिति कोई नई समिति नाम-निर्दे-भित-होने नक कार्य करनी रहेगी।
 - (3) समिति में श्राकस्मिक रूप में रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति सभापित द्वारा की जायेगी।
- 212 (ग) समिति का सभापति.--(1) ममिति का सभापति समिति के सदस्यों में से सभा-पित द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

परन्तु यदि उपसभापति समिति का सदस्य हो तो उसे समिति का समापति नियुक्त किया जाएगा ।

- (2) यदि समिति का सभापित किसी कारण से कार्य करने में श्राप्तमर्थ हो तो सभापित उसी प्रकार से उसके स्थान पर समिति का एक श्रान्य सभापित नियुक्त कर सकेगा।
- (3) यदि समिति का सभापति किसी बैठक से श्रनुपस्थित रहे तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में समिति के सभापति के रूप में कार्य करने के लिये चुनेगी।
 - 212 (घ) गणपर्ति.--(1) समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति पांच होगी।
- (2) समिति का सभापति प्रथमतः मत नहीं देगा, परन्तु किसी विषय पर मतों की संख्याः समान होने की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

212 (७०) साक्ष्य लेने अथवा पत्रों, ग्राभिलेखों या प्रलेखों को मंगाने की शक्ति.—
(1) यदि समिनि श्रपने कर्नेब्य-पालन के लिये व्यक्तियों को उपस्थित अथवा पत्र श्रथवा ग्राभिलेख, प्रस्तुत करना भ्रावश्यक समझे तो उसे ऐसा मार्ग अपनाने की शक्ति होगी:

परन्तु सरकार किसी प्रलेख को प्रस्तुत करने से इस द्राधार पर इंकार कर सकेगी कि उसका प्रकट किया जाना राज्य की सुरक्षा या हित के प्रतिकृत होगा।

- (2) इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सचिव द्वारा हस्ताक्षरित **धादेश के** द्वारा किसी साक्षी को श्रामंत्रित किया जा सकेगा श्रौर वह ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करेगा जो सिमिति के उपयोग के लिये श्रपेक्षित हों।
- (3) यह समिति के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि वह श्रपने सामने दिये गये किसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय माने।
- 212(च) प्रतिवेदन का उपस्थापन.—सिमिति का प्रतिवेदन राज्य सभा में सिमिति के सभापति द्वारा या उसकी श्रनुपस्थिति में मिमिति के किसी सदस्य द्वारा उपस्थित किया आयेगा।
- 212(छ) प्रकिदा का विनिद्यमन समिति, समिति में ग्राश्यासनों, प्रतिजाश्रों, वचनों इत्यादि के उसकी प्रश्न पर विचार से संबंधित सभी थिपयों के बारे में ग्रपनी प्रक्रिया स्वयं-निर्धा-ंरित करेगी।

बी० एन० बनर्जी, मचिव ।